

कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/२१५ /वाचक/ 2018

सूरजपुर, दिनांक ०६/०७/२०१८

संशोधित प्रमाण पत्र

आवेदक कार्यालय कार्यपालन अभियंता, (अउदा) निर्माण/संभाग, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. कोरबा को सतपता (विश्रामपुर) से कौशलपुर (रामानुजनगर) तक पारेषण लाईन हेतु जिला सूरजपुर में सूरजपुर वनमण्डल अन्तर्गत सलका, पोड़ी, जोबगा, केतका, आमगांव, पटना, चन्द्रिकापुर, रामपुर, दवना, सरईपारा एवं रामानुजनगर ग्राम के वनभूमि व्यपवर्तन हेतु ०.६८७ हे. वनभूमि एवं ४.२५३ हे. राजस्व वनभूमि के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ का पालन प्रतिवेदन। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि:-

१. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम २००६ में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र सतपता (विश्रामपुर) से कौशलपुर (रामानुजनगर) तक की वनभूमि (संरक्षित- ०.६८७ हे.) एवं राजस्व वन भूमि ४.२५३ हे. कुल रकबा ४.९४ हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम-सलका, पोड़ी, जोबगा, केतका, आमगांव, पटना, चन्द्रिकापुर, रामपुर, दवना, सरईपारा, रामानुजनगर तहसील सूरजपुर एवं रामानुजनगर में स्थित हैं, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता प्राप्त धारक का नाम	रकबा(हे.में)
१	सलका	निरंक	निरंक
२	पोड़ी	निरंक	निरंक
३	जोबगा	निरंक	निरंक
४	केतका	निरंक	निरंक
५	आमगांव	निरंक	निरंक
६	पटना	निरंक	निरंक
७	चन्द्रिकापुर	१. मोती आ. सपूरन जाति गोंड़ २. साधारण आ. सपूरन गोड़	०.१५ हे. ०.३२ हे.
८	रामपुर	निरंक	निरंक
९	दवना	निरंक	निरंक
१०	सरईपारा	निरंक	निरंक
११	रामानुजनगर	निरंक	निरंक

२. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम २००६ की धारा ३(१)(ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

३. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ की धारा ३(२) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

(के.सी.देवसेनापति)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला-सूरजपुर